EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 12 January 2026

देश सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए गए भगवान दास

डा. भगवान दास का जन्म 1869 में आज ही वाराणसी में हुआ था। वह बहुत मेधावी छात्र थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सरकारी कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। सरकारी नौकरी छोड़ कर 1894 में वह थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कई बार जेल गए। भगवान दास ने डा एनी बेसेंट के साथ मिलकर सेंट्रल हिंदू कालेज की स्थापना की। यह संस्थान वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। भगवान दास को 1955 में देश का सवोच्च्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। गया।

सांप्रदायिक दंगों से दुखी महात्मा गांधी ने दिया अपना आखिरी भाषण

1948 में आज ही महात्मा गांधी ने अपना आखिरी भाषण दिया था। इसके बाद वह 13 जनवरी से अनशन पर चले गए थे। 12 जनवरी की शाम को दिए अपने भाषण में गांधीजी ने कहा था कि सांप्रदायिक दंगों में बर्बादी देखने से बेहतर मौत को गले लगा लेना है। वह देश के विभाजन के बाद हो रहे सांप्रदायिक दंगो से दुखी थे।

अगर भारत को टेक्नोलाजी में आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करना है तो सरकारी संस्थानों को रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन में बड़ी भूमिका निभानी होगी।

— सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन, नीति आयोग

Sci & Tech

विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में शुभांशु शुक्ला ने कहा

विफलताओं से उबरना सीखें और प्रगति की ओर बढ़ते रहें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जनवरी।

विफलताओं से उबरकर वापस लौटना, कभी संतुष्ट न होना और प्रगति की ओर लगातार बढ़ते रहना। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के दौरान शुभांशु शुक्ला ने रविवार को युवाओं को यह संदेश दिया। शुक्ला ने फिल्म 'फाइंडिंग निमो' के संदेश को याद करते हुए कहा कि तैरते रहो, कभी हार मत मानो। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे चुनौतियों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि सफलता हासिल हो सके। कार्यक्रम में शुभांशु शुक्ला के साथ प्रशांत नायर भी मौजूद रहे।

संवाद के दौरान शुक्ला ने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है। हम आमतौर पर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है उसका सम्मान करें, उसका सर्वोत्तम उपयोग करें और सफलता बिना मांगे आपके पास आती रहेगी।

उन्होंने मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने अठारह दिन के अनुभव साझा किए। शुक्ला ने बताया कि जिस क्षण इंजन चला, ऐसा लगा जैसे मैं जो कुछ जानता था, सब भूल गया। कंपन इतना तीव्र था कि अंदर तक शरीर हिल गया।

नायर पिछले साल एक्सिओम-4 मिशन के लिए शुक्ला के साथ प्रशिक्षण ले चुके हैं। उन्होंने युवाओं से 'भारत' को अपना आदर्श और प्रेरणा बनाने का आग्रह किया। साथ ही देश की भलाई के लिए काम करने को कहा। गगनयान मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री में से एक नायर ने युवाओं से कहा कि जब भी आप कुछ करें, तो याद रखें कि भारत को विकसित बनाने में एक व्यक्ति का साथ नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को एस साथ आना होगा। भारत को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानकर, जो भी करें, बेहतरी के लिए करें। शुक्ला ने मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने अठारह दिन के अनुभव साझा किए। बचपन में एक एअर शो से प्रभावित होने वाले शुक्ला ने बताया कि वे संयोग से पायलट बने क्योंकि उन्होंने दोस्तों की देखादेखी में रक्षा क्षेत्र के पाठ्यक्रम का प्रपत्र भरा। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। संवाद में शुक्ला ने युवाओं को अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें दिखाई। यात्रा के पल को साझा करते हुए शुक्ला ने बताया कि जिस क्षण इंजन शुरू हुए, ऐसा लगा जैसे मैं जो कुछ जानता था, सब भूल गया। कंपन इतना तीव्र था कि अंदर तक शरीर हिल गया। सिर्फ साढ़े आठ मिनट में, हम शून्य से 28,500 किमी प्रति घंटा की गति पर पहुंच गए। आप सांस अंदर नहीं ले सकते, केवल बाहर निकाल सकते हैं। आप पेट से सांस लेते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष उड़ान से पहले वर्षों का प्रशिक्षण आवश्यक है।

Jansatta Page

दिग्गजों ने माना, एआई की वजह से निखर रही है प्रतिभा

सर्वेक्षण : एआई अपनाने में अमेरिका से आगे भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय आईटी दिग्गज एआई टूल्स को सिर्फ अपना नहीं रहे बल्कि एजेंटिक एआई के जरिए दुनिया में तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। एक सर्वे से पता चला कि भारत एजेंटिक एआई को अपनाने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों से काफी आगे है।

प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म थॉटवर्क्स की रिपोर्ट के अनुसार, 86% आईटी दिग्गजों ने माना कि एआई की वजह से प्रतिभा निखर रही है। यह नौकरियां नहीं छीन रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव कौशल और काम की गति को बढ़ाने में दिख रहा है। यह सर्वेक्षण सात देशों के 3,500 अधिकारियों पर किया गया, जिसमें 500 प्रतिभागी भारत से थे। एजेंटिक एआई को अपनाने के मामले में भारत 48 प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे आगे है। यह अमेरिका (28%) और ऑस्ट्रेलिया (23%) जैसे बाजारों से बिल्कुल अलग स्थिति है। 57 प्रतिशत कंपनियों ने बताया कि मानव-एआई सहयोग से संस्थाओं में भूमिकाओं और पदों में बढ़ोतरी हुई है। एजेंटिक एआई उन सिस्टम पर आधारित है जो स्वतंत्र सोचने, तर्क, काम करने में सक्षम है। एआई का उन्नत रूप है, जो जवाब ही नहीं देता, एक एजेंट की तरह स्वतंत्र रूप से काम पूरा करता है। यह बुकिंग, शॉपिंग जैसे काम को अंजाम दे सकता है। 49% दिग्गजों ने उम्मीद जताई कि पांच वर्षों में भारतीयों के राजस्व में 15% की वृद्धि होगी।

भारतीयों का नजरिया सकारात्मक

यह रुझान दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां अब केवल एआई टूल का उपयोग नहीं कर रहीं, बल्कि वे पूरी तरह से एआई-आधारित बिजनेस मॉडल की ओर बढ़ रही हैं। सर्वे के दौरान 10 में नौ लोगों ने कहा कि एआई लोगों की प्रतिभा को निखार रहा है।

पीएसएलवी-सी62 प्रक्षेपण को तैयार

आंध्र प्रदेश

■ **इसरो आज लॉन्च करने जा रहा है इस साल का पहला उपग्रह**

श्रीहरिकोटा, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पीएसएलवी) रॉकेट सी62 मिशन के प्रक्षेपण के लिए रविवार को साढ़े बाईस घंटे की उल्टी गिनती शुरू की। यह इस साल का पहला मिशन है।

इसके जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ-साथ 14 अन्य सह उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए भेजे जा रहे इस मिशन में 14 घरेलू और विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

इसरो ने बताया कि 260 टन के भार वाले पीएसएलवी-सी62 रॉकेट का प्रक्षेपण सोमवार को 10.18 बजे के लिए निर्धारित किया गया है। उल्टी गिनती रविवार को दोपहर 12.48 बजे शुरू हुई। कुल अवधि 22 घंटे 30 मिनट है। पीएसएलवी-सी62/ईओएस-एन1 मिशन सबसे पहले थाईलैंड और ब्रिटेन द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा, जिसके बाद प्रक्षेपण के लगभग 17 मिनट बाद 13 अन्य उपग्रहों को सूर्य-समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

इसके बाद, रॉकेट के चौथे चरण (पीएस4) के अलग होने और स्पेनिश स्टार्टअप से संबंधित लगभग 25 किलोग्राम वजनी केस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर (केआईडी) कैप्सूल स्थापित होगा। ऐसा प्रक्षेपण के दो घंटे से अधिक समय बाद होने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक, वैज्ञानिक रॉकेट के चौथे चरण को फिर से प्रणोदित करेंगे, ताकि केआईडी कैप्सूल को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हुए प्रदर्शित किया जा सके।

Hindustan Page

अरुणाचल प्रदेश में मेंढकों की दो नई प्रजातियां मिलीं

ईटानगर, एजेंसी। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढकों की दो नई प्रजातियां खोजी हैं। वैज्ञानिकों ने इनका नाम सोमन स्लेंडर और मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग बताया है।

ये मेंढक बहुत छिपी हुई, पहाड़ी और जंगलों वाली जगहों में रहते हैं, इसलिए अब तक वैज्ञानिकों की नजर में नहीं आए थे। तीन साल से ज्यादा समय से इनकी खोज की जा रही थी। अब तक इस प्रजाति के सभी मेंढक ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में मिलते थे, लेकिन ये दोनों नई प्रजातियां नदी के उत्तर में पाई गईं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि नदियां जीवों के फैलाव को कैसे रोकती या बदलती हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट, शरीर की बनावट, आवाज और हड्डियों के स्कैन के आधार पर पुष्टि की कि ये नई प्रजातियां हैं।

सोमन स्लेंडर

मेचुका स्लेंडर

सभी दिशाओं में मार करने में सक्षम होगी ब्रह्मोस-2 मिसाइल

हैदराबाद। भारतीय वैज्ञानिकों ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस-2 के लिए लंबी अवधि वाले इंजन ग्राउंड टेस्ट का 12 मिनट से अधिक समय तक सफल ग्राउंड टेस्ट पूरा किया। यह दुश्मन को हर दिशा में मार गिराएगी। इस सफल ग्राउंड टेस्ट के बाद इंजन अब वास्तविक उड़ान परीक्षण के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके 2026 के अंत या 2027 में पहला वास्तविक फ्लाइट टेस्ट होने की संभावना है। इस सफलता से आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा मिलेगा।

सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी अपना पहला सैटेलाइट CGUSAT-1 लॉन्च करेगी

सी.वी.रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के ईस्टर्न जोन की पहली यूनिवर्सिटी बनकर इतिहास रचेगी जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी। यूनिवर्सिटी का पहला सैटेलाइट, CGUSAT-1, भारत सरकार के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) C-62 का इस्तेमाल करके स्पेस में लॉन्च किया जाएगा।

इस बड़ी कामयाबी की नींव चार साल पहले रखी गई थी, जब यूनिवर्सिटी के स्पेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत भारत सरकार का लाइसेंस वाला सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन (कॉल साइनः VU2CGU बनाया गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग के हिस्से के तौर पर, CGU के एडवाइजर प्रोफेसर सुनील कुमार सारंगी ने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए सैटेलाइट डेवलपमेंट में दुनिया भर में सबसे अच्छी प्रैक्टिस की स्टडी करने के लिए टेक्नियन यूनिवर्सिटी और हर्जलिया साइंस सेंटर, इजराइल का दौरा किया।

कालाजार उन्मूलन की दिशा में हुए कार्यों का बनेगा डोजियर

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार में कालाजार उन्मूलन को औपचारिक मान्यता दिलाने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। राज्य सरकार कालाजार उन्मूलन से संबंधित एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है, जिसका वैलिडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) से कराया जाएगा।

इस डोजियर में राज्य में कालाजार उन्मूलन को लेकर अब तक किए गए सभी महत्वपूर्ण प्रयासों, उपलब्धियों और आंकड़ों को संकलित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिहार ने वर्ष 2022 में ही कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। इसके बावजूद प्रति 10 हजार आबादी पर एक से कम कालाजार रोगी मिलने के मानक के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन के लिए डोजियर तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह विस्तृत डोजियर तैयार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन से वैलिडेट भी कराएगा सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आंकड़ों को संकलित किया जाएगा

डोजियर में वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक कालाजार उन्मूलन के लिए किए गए सभी कार्यों का क्रमबद्ध और साक्ष्य-आधारित विवरण शामिल होंगे। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव, घर-घर जाकर रोगियों की खोज, संदिग्ध मामलों की जांच, पुष्टि होने पर उपचार तथा त्वचा कालाजार (पीकेडीएल) के रोगियों की पहचान और इलाज से संबंधित आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही निगरानी व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक जागरूकता अभियान और स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका का भी उल्लेख किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह डोजियर न केवल राज्य की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि भविष्य में पुनः संक्रमण की आशंका को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को भी रेखांकित करेगा। डोजियर के तैयार होने के बाद इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन को भेजा जाएगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा इसका वैलिडेशन किया जाएगा। वैलिडेशन मिलने के बाद बिहार को कालाजार उन्मूलन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक सफल माडल के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी।

Dainik Jagaran Page

BIHAR

राजगीर: पहली बार जनवरी में सूखीं जलधाराएं

राजगीर, निज प्रतिनिधि। प्राचीन काल से ऐतिहासिक राजगीर की पहचान 22 कुंड और 52 धाराएं रही हैं। जनवरी में भीषण ठंड के मौसम में गंगा-जमुना कुंड की दो गर्म जल धाराओं के सूखने से लोग हैरान और चिंतित है। सर्द मौसम में पहली बार कुंड की धाराओं से पानी नहीं आ रहा है। कुछ साल पहले गर्मी में इन कुंडों की धाराएं कुंद पड़ी थीं।

जानकारों का कहना है कि कुंड क्षेत्र में बोरिंगों की संख्या अधिक होने से ऐसे भयावह हालात बने हैं। 18 मई से राजगीर में एक माह का मलमास मेला शुरू होने वाला है और स्थानीय लोग चिंतित हैं कि कुंड में पानी नहीं होने पर श्रद्धालु स्नान व पूजा-पाठ कैसे करेंगे। सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता जयदेव प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2010 में केन्द्रीय टीम ने कुंड के जलस्त्रोतों और धाराओं की स्थिति का अध्ययन किया था। टीम ने कई अनुशंसाएं की थीं। लेकिन, विशेष काम नहीं हुआ। ब्रह्मकुंड पंडा कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि आसपास में उच्चप्रवाही बोरिंग लगाने से कुंडों के जलस्त्रोतों का पानी भू-गर्भ में चला जाता है। ऐसे में बरसात के बाद कुंड और धाराओं के लिए पानी पहाड़ में नहीं रह पाता है।

कुंड क्षेत्र के आस-पास अधिक बोरिंग बड़ी वजह

22 कुंड, 52 धाराएं आदिकाल से राजगीर की रही है पहचान

राजगीर में गंगा-जमुना कुंड की बंद दो धाराएं। मलमास में श्रद्धालु कैसे करेंगे स्नान।

क्या है मान्यता और महत्व

पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने यहीं यज्ञ किया था। उसी वक्त उनके मानस पुत्र राजा वसु ने 22 कुंडों, 52 धाराओं का निर्माण करवाया था। वैभारगिरी से आने वाली जलधारा (ब्रह्मकुंड) का तापमान 45 से 50 डिग्री होता है। माना जाता है कि कुंड में स्नान से त्वचा रोग, जोड़ों में दर्द सहित अन्य व्याधियां दूर होती हैं। यहां मकर संक्रांति और मलमास में स्नान का विशेष महत्व है।

"सिंचाई विभाग की टीम ने गंगा-जमुना कुंड का अध्ययन किया है। रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्य होंगे। वहीं, कुंड क्षेत्र के निट उच्चप्रवाही बोरिंग कराने वालों पर कार्रवाई होगी।
-आशीष नारायण, एसडीओ, राजगीर

Hindustan Page

16वीं यात्रा : मुख्य सचिव ने सभी डीएम और विभागों को तैयारी के दिए निर्देश

सीएम की समृद्धि यात्रा 16 से, संवाद और समीक्षा करेंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी जिलों में जाएंगे। वहां की योजनाओं-कार्यक्रमों की धरातल पर क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। साथ ही समीक्षा बैठक भी करेंगे और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। यात्रा के दौरान वह जनसंवाद भी करेंगे।

मुख्यमंत्री की यह 16वीं यात्रा होगी। नीतीश कुमार अब-तक अपनी सभी यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करते रहे हैं। इस बार भी उम्मीद है कि वे पश्चिम चंपारण से ही समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसकी जिलेवार तिथि एक-दो दिनों में जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान मुख्य रूप से प्रगति यात्रा के दौरान लिये गये निर्णयों और उनके निर्देशों की स्थिति को देखेंगे। इसके साथ ही सात निश्चय से संबंधित योजनाओं तथा जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे।

जिले की प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन भी करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम भी होंगे। जिलास्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों-प्रधान सचिवों के साथ ही जिलों के प्रभारी सचिव, डीजीपी, सभी डीएम-एसपी को पत्र लिखा है।

उन्होंने जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा है कि समृद्धि यात्रा के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों की आवश्यक तैयारी समय पर करना सुनिश्चित करें।

स्थल निरीक्षण के समय संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी मौजूद रहेंगे। जिलों की समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक, निर्धारित विषयों से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित रहेंगे।

➤ गोलघर परिसर P 07

पश्चिम चंपारण से हो सकती है शुरुआत

गोलघर परिसर में रविवार को जायजा लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सीएम के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह व अन्य।

23 दिसंबर 2024 को प. चंपारण से प्रगति यात्रा शुरू की थी

अब-तक की नीतीश की यात्रा और प्रारंभ की तिथि

न्याय यात्रा	12 जुलाई 2005
विकास यात्रा	09 जनवरी 2009
धन्यवाद यात्रा	17 जून 2009
प्रवास यात्रा	25 दिसंबर 2009
विश्वास यात्रा	28 अप्रैल 2010
सेवा यात्रा	09 नवंबर 2011
अधिकार यात्रा	19 सितंबर 2012
संकल्प यात्रा	05 मार्च 2014
संपर्क यात्रा	13 नवंबर 2014
निश्चय यात्रा	09 नवंबर 2016
विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा	12 दिसंबर 2017
जल-जीवन-हरियाली यात्रा	03 दिसंबर 2019
समाज सुधार अभियान	22 दिसंबर 2021
समाधान यात्रा	04 जनवरी, 2023
प्रगति यात्रा	23 दिसंबर 2024

राज्य के विश्वविद्यालय पांच-पांच गांव गोद लेंगे

- लोकभवन में आयोजित बैठक में कुलपतियों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने दिए निर्देश
- विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, कर्मियों की रिक्ति फरवरी के प्रथम सप्ताह तक भेजने के लिए कहा गया

शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करें, रिजल्ट देने में देरी न हो

राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए निर्धारित शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू करें। परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन में देरी नहीं हो। बैठक के दौरान बताया गया कि जयप्रकाश नारायण विवि छपरा और केएसडीएस में विभिन्न विषयों में परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन में 14 माह से 20 माह तक देर हो रही है। वहीं, ललित नारायण मिथिला विवि दरभंगा, आर्यभट्ट ज्ञान विवि, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और पूर्णिया विवि में शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर में 6 से 8 माह तक की देर हो रही है। विवि को एक और दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया गया।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के पांच-पांच गांवों को गोद लेकर उन्हें शैक्षणिक रूप से उन्नत बनाएं। इससे संबंधित उन्नत भारत अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराएं।

इन गांवों के लोगों को शिक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करें, ताकि लोगों का जीवन आसान हो। ये गांव आदर्श गांव के रूप में पहचाने जाएं। पर्यावरण की भी सुरक्षा हो। गांव के लोग सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम हो सकें। लोकभवन में रविवार को हुई बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को माननीय उच्च न्यायालय एवं बिहार लोक भवन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े हुए बिहार विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए अपेक्षित रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में समर्थ मॉड्यूल, अपार आईडी, विभिन्न वित्तीय मुद्दों आदि की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिये गए। बताया गया कि विश्वविद्यालयों के पास 1371 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र देना लंबित है। जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया। बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे।

Dainik Jagaran Page

बिहार में तीन वर्षों के अंदर होंगे 11 लाख कृषि कनेक्शन

कार्ययोजना तैयार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना के तहत बिजली कंपनी ने किसानों को बिजली कनेक्शन देने की कार्ययोजना तैयार कर ली है। कंपनी ने अगले तीन वर्षों में कृषि कनेक्शन की संख्या 11 लाख करने का निर्णय लिया है।

किसानों को निःशुल्क कनेक्शन देने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता (जीएम) तक को जिम्मेदारी दी गई है। इंजीनियरों को साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य दिया गया है। मुख्यालय स्तर के अधिकारी नियमित तौर पर इस अभियान की निगरानी करेंगे, ताकि आवेदन देने के बाद किसानों को बिजली कनेक्शन मिल सके। कंपनी अधिकारियों के अनुसार, बिहार में हर साल 16 फीसदी तक कृषि कनेक्शन में वृद्धि होने का अनुमान है। आकलन के मुताबिक अगले तीन वर्षों में राज्य में कृषि कनेक्शन की संख्या 11 लाख से अधिक हो जाएगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे बिजनेस प्लान में बिजली कंपनी ने पहले ही बता रखा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर बिहार में तीन लाख 11 हजार 71 तो दक्षिण बिहार में पांच लाख चार हजार 929 कृषि कनेक्शन की संख्या यानी आठ लाख से अधिक हो जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर बिहार में तीन लाख 35 हजार 956 तो दक्षिण बिहार में कृषि कनेक्शन की संख्या छह लाख 15 हजार 156 यानी नौ लाख 51 हजार से अधिक हो जाएगी। यानी एक साल में डेढ़ लाख से अधिक किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2027-28 में उत्तर बिहार में तीन लाख 62 हजार 833 तो दक्षिण बिहार में सात लाख 49 हजार 445 यानी 11 लाख 12 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन हो जाएंगे। यानी एक साल में दो लाख से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जाएंगे।

- कनीय से लेकर मुख्य अभियंता तक की जिम्मेदारी तय

किसानों को मिल रही सस्ती बिजली

कंपनी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई कार्ययोजना में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता (जीएम) को जिम्मेदारी दी है। इंजीनियरों को कहा गया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ इलाकों में कृषि कनेक्शन की संख्या में तेजी से वृद्धि करें। सरकार के स्तर पर आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। ऐसे में अगर कोई किसान कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो स्थल निरीक्षण कर उन्हें अविलंब बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अभी कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार की ओर से 92 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सोलर बिजली देने की योजना पर भी हो रहा काम

बिहार के किसानों को सोलर बिजली से पटवन की सुविधा देने पर भी काम चल रहा है। कृषि फीडर को सोलर से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत इस पर काम किया जा रहा है। शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, गयाजी, कैमूर, रोहतास, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, सारण, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, सहरसा, जहानाबाद, जमुई, बक्सर, खगड़िया, पूर्णिया, अरवल, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, लखीसराय और सीवान में इस पर काम चल रहा है।

Hindustan Page

उपेक्षा | कुल लोन का कृषि को 28 फीसदी, जबकि एमएसएमई को 51 फीसदी दिया, 21 जनवरी को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

बिहार के बैंकों को कृषि से ज्यादा एमएसएमई लोन देने में रुचि

■ कौशलेंद्र मिश्र

पटना। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की रुचि कृषि से अधिक सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों (एमएमएमई) को लोन देने में अधिक है। राज्य में वार्षिक साख योजना के तहत तय लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर 2025 तक दिए गए कुल लोन का कृषि क्षेत्र में 28 फीसदी, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में 51 फीसदी लोन दिया गया है। राज्य में खेती और किसानी की उपेक्षा करने वाले बैंकों में निजी और सरकारी बैंक दोनों शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र में 1,12,000 करोड़ लोन दिए जाने का लक्ष्य तय है जबकि सितंबर 2025 तक इस क्षेत्र में मात्र 31,120 करोड़ रुपये ही लोन के रूप में दिया गया है। जो कि लक्ष्य का 28 फीसदी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी सितंबर, 2024 तक तय लक्ष्य का मात्र 24 प्रतिशत ही लोन दिया गया था, जबकि एमएसएमई क्षेत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,19,000 करोड़ रुपये लोन दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध सितंबर, 2025 तक 61,175 करोड़ रुपये का लोन के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। यह लक्ष्य का 51 फीसदी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस अवधि में तय लक्ष्य का 43 फीसदी लोन एमएमएमई क्षेत्र में दिया गया था। स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष में सितंबर, 2025 तक कृषि क्षेत्र की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र को करीब दोगुनी राशि उपलब्ध कराई गई है।

3.36 लाख करोड़ के एसीपी का लक्ष्य हासिल किया जाना है दो माह में

- खेती और किसानी की उपेक्षा करने वाले बैंकों में निजी और सरकारी दोनों शामिल

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसीपी के लक्ष्य और उपलब्धि (करोड़ में)

प्रदर्शन	कृषि	एमएमएमई	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	कुल प्राथमिक क्षेत्र	गैर प्राथमिक क्षेत्र	कुल एसीपी
लक्ष्य	1,12,000	1,19,000	9000	2,40,000	96,000	3,36,000
उपलब्धि	31,126	61,175	2688	94,989	48,126	1,43,115
प्रतिशत	27.79%	51.41%	29.87%	39.58%	50.13%	42.59%

बैंकर्स समिति की बैठक में साख-जमा अनुपात बढ़ाने पर भी किया जाएगा विमर्श

जानकारी के अनुसार, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की दिसंबर, 2025 में प्रस्तावित बैठक अब 21 जनवरी को पटना में होगी। बैठक में राज्य के किसानों, पशुपालकों, मछलीपालन, लघु एवं बड़े उद्योगों के लिए बैंकों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली पूंजी पर चर्चा होगी। इसमें राज्य में अपेक्षा से बेहद कम साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) होने एवं किसानों एवं कृषि आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बाजार तक उपलब्धता बढ़ाने को लेकर लोन के प्रवाह में कमी के मुद्दे पर जवाब भी तलब किया जाएगा।

बैठक में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक साख योजना (एसीपी) का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जाएगा। अगले दो माह में राज्य में दो माह में 3.36 लाख करोड़ के एसीपी का लक्ष्य हासिल किया जाना है।

पीएम रोजगार सृजन योजना : देश के 104 जिलों पर मंत्रालय की रिपोर्ट जारी

पांच साल में बिहार से 3052 को ही मिला लोन

संवाददाता, पटना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमइजीपी) में बिहार के प्रोजेक्ट को औसत से कम मंजूरी मिली है. यहां राष्ट्रीय औसत से कम संख्या में लोन बांटे गये हैं. इसे चिंता की बात माना जा सकता है. बिहार से भेजे गये लोन प्रस्तावों में केवल 23% प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. जिन प्रोजेक्ट पर लोन बांटे गये उनकी संख्या केवल 15-16% ही है, जबकि पूरे पीएमइजीपी में पूरे देश में आवेदन की तुलना में लोन बांटने का औसत प्रतिशत 27 से

अधिक है. बिहार में अभी तक लोन केवल 3052 लोगों को ही दिये गये. आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार के कुल 104 जिलों की रिपोर्ट हाल में सामने आयी है. ये सारे तथ्य से उसी से संबंधित हैं.

पीएमइजीपी योजना में बिहार के तीन विशेष जिले शामिल किये गये थे. यह जिले पटना, मधुबनी और गया हैं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिहार के तीन जिलों गया, मधुबनी और पटना से एक अप्रैल, 2020 से 10 जनवरी तक कुल 19568 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजे गये. इनमें से 4548 केसों को मंजूरी दी गयी. हालांकि, अभी तक लोन केवल 3052 लोगों को ही दिये गये. इतने लोगों को इसकी अवधि के दौरान करीब 100 करोड़ के लोन दिये गये हैं, जबकि पूरे भारत के 104 जिलों से 304190 प्रस्ताव गये. इनमें 113713 लोगों के आवेदन मंजूर हुए. इसमें से अभी तक केवल 82556 लोगों को लोन बांटे जा चुके हैं.

पटना, गया और मधुबनी जिले हैं शामिल

रिपोर्ट के अनुसार, गया से एक अप्रैल, 2020 से 11 जनवरी, 2026 तक 5870 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए गये. इनमें 1301 लोगों के प्रोजेक्ट मंजूर हुए. इनमें से अभी तक केवल 1002 लोगों को ही लोन मिल सके हैं. मधुबनी के 5718 लोन प्रस्ताव गये. इनमें से 1288 केस मंजूर हुए, जबकि इनमें से केवल 807 लोगो को ही लोन मिल सके. जहां तक पटना जिले का सवाल है, यहां से कुल 7980 लोगों के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजे गये. इनमें से 2019 केस मंजूर हुए, लेकिन लोन अभी तक केवल 1243 प्रोजेक्ट को ही मिल सके हैं. बता दें कि पीएमइजीपी के तहत केंद्र ने पूरे देश के 104 जिलों की खास रिपोर्ट तैयार की. उनका सत्यापन किया, उसमें यह जानकारी मिली है.

Dainik Bhaskar

‘मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर पहुंचा’

पटना। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सतत पहल और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से बिहार आज मछली उत्पादन में देश के चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। 2013 में बिहार नौवें स्थान पर था। मछली उत्पादन में लगभग 100 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि यह साबित करती है कि जब सरकार विकास पर काम करती है।

बीच गेम्स में बिहार की पुरुष सेपक टाकरा टीम बनी ओवरऑल चैंपियन

खेलो इंडिया, पटना

दीव में पांच से दस जनवरी तक आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार की पुरुष सेपक टाकरा टीम ओवरऑल चैंपियन बनी. वहीं, महिला वर्ग में बिहार की टीम तीसरे स्थान पर रही. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने बताया कि बिहार की पुरुष सेपक टाकरा टीम ने क्वाड इवेंट में स्वर्ण और टीम इवेंट में रजत पदक जीत कर ओवरऑल चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया. बिहार की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इवेंट में रजत पदक के साथ ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही. खेलो इंडिया बीच गेम्स में बीच मलखंभ और टग ऑफ वार प्रदर्शनी खेल थे और बीच फुटबॉल, बीच वालीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टाकरा, बीच पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग प्रतियोगिता वाले खेल थे.

बिहार की कबड्डी टीम का हुआ भव्य स्वागत

पटना. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-14 की कबड्डी में पहली बार उप विजेता बनकर लौटी बिहार की टीम का रविवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने स्टेशन पर स्वागत किया. उन्होंने बताया कि किसी भी टीम का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाते वक्त सम्मान के साथ विदा और जीत कर आने पर स्वागत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किया जाता है. बिहार नेशनल स्कूल गेम्स कबड्डी में पहली बार कोई पदक जीता है.

बिहार को बंदी सुधार के लिए मिला पुरस्कार

संवाददाता, पटना

जेल सुधार और बंदी पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए कारा. एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नयी दिल्ली में आयोजित 105वीं स्कॉच बैठक के दौरान ‘गवर्निंग विकसित भारत’ कार्यक्रम में यह पुरस्कार बिहार को प्रदान किया गया. जेलों के भीतर डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर प्रशिक्षण और बंदी पुनर्वास कार्यक्रमों के सफल संचालन को देखते हुए कारा विभाग को यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है.राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है. इसके तहत जेल परिसरों में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की गयी हैं, जहां बंदियों को बुनियादी से लेकर उन्नत स्तर तक की डिजिटल जानकारी दी जा रही है. कारा. एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय द्वारा एनआइएलइटी के माध्यम से बंदियों को विभिन्न कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं और सफल प्रशिक्षण के बाद उन्हें मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र भी दिये जा रहे हैं.

पुरस्कार लेते जेल आइजी, साथ में हैं कारागार सेवा के अन्य अधिकारी.

सशक्त स्थायी समिति में पार्षद योजना पर मुहर लगेगी

बैठक आज

- विकास और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा
- नगर सचिव की ओर से आधिकारिक पत्र जारी

टना। पटना नगर निगम की सशक्त थायी समिति की 19वीं साधारण ठक सोमवार को होगी। इसमें पार्षद ोजना 4.0 की राशि को आवंटित रवाने के प्रमुख मुद्दों पर विमर्श और नर्णय भी संभावित है।

इस योजना के अंतर्गत सभी 75 वार्ड ार्षद को विकास कार्य के लिए एक रोड़ रुपए दिए जाने हैं।इस बार वित्तीय र्ष के 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी ह राशि नहीं मिली है। महापौर ार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक के बारे में पटना नगर निगम के नगर सचिव की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। स्थायी समिति के सभी सदस्यों को भी पत्र जारी किया गया है इसमें महापौर, उप-महापौर एवं सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। साथ ही नगर निगम से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों, योजनाओं एवं प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

Hindustan Page

NATIONAL

ए आर रहमान ने जीता गोल्डन ग्लोब अवार्ड

2009 में आज ही ए आर रहमान ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। यह उपलब्धि पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। उनको पुरस्कार स्लमडाग मिलेनियर फिल्म के संगीत के लिए मिला था। मनोरंजन जगत से जुड़ा आस्कर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है।

जागरण विशेष
राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी)

जहां जन्मे विचार, वहां आज भी 'जीवित' हैं विवेकानंद

उत्तर कोलकाता की संकरी गलियों से लेकर हुगली के तटों तक उनका जीवन और दर्शन आज भी एक जीवित चेतना की तरह धड़कता है

कोलकाता की संकरी गलियों में कदम रखते ही अगर कोई स्वर आज भी हवा में घुला महसूस होता है, तो वह है- 'उत्तिष्ठत, जाग्रत' का आह्वान। यह स्वर किसी स्मारक की दीवारों में कैद नहीं, बल्कि उन स्थानों की मिट्टी में रचा-बसा है, जहां नरेन्द्रनाथ दत्त ने स्वयं को स्वामी विवेकानंद के रूप में पहचाना।

12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती केवल एक महान संन्यासी की स्मृति नहीं, बल्कि उन स्थलों की यात्रा का निमंत्रण है, जहां भारत ने आधुनिक आत्मविश्वास और सेवा का मार्ग पाया। विवेकानंद को जानना हो तो किताबें पर्याप्त नहीं, उन जगहों तक जाना जरूरी है, जहां विचार जीवन बन गए। कोलकाता और काशी केवल नक्शे पर बिंदु नहीं, बल्कि चेतना के पड़ाव हैं। यहां जाना केवल यात्रा नहीं, स्वयं से संवाद है।

विवेकानंद आज भी युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। उनकी स्मृतियां संग्रहालयों में कैद नहीं, वे गलियों, घाटों और पर्वतों में आज भी सांस लेती हैं। इस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद को केवल स्मरण न करें, बल्कि उन स्थानों की ओर कदम बढ़ाएं, जहां उनके विचार जन्मे व आज भी जीवित हैं।

कोलकाता : केवल नरेन्द्रनाथ दत्त का जन्मस्थल नहीं, बल्कि उनके चिंतन की है प्रयोगशाला

सिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास, जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ ● इंटरनेट मीडिया

कोलकाता केवल विवेकानंद का जन्मस्थल नहीं, बल्कि उनके चिंतन की प्रयोगशाला है। उत्तर कोलकाता का सिमला स्ट्रीट स्थित पैतृक आवास, जोकि आज का स्वामी विवेकानंद सरणी है, उस बालक नरेन्द्र का साक्षी है, जिसने संगीत, दर्शन और विज्ञान को एक साथ साधा। यहां रखी पुस्तकें, पत्र और वायलिन बताते हैं कि विवेकानंद के लिए आध्यात्मिकता पलायन नहीं थी, बल्कि आधुनिकता के साथ संवाद थी। यही भूमि बताती है कि वह संन्यासी होने से पहले एक जाग्रत नागरिक थे, जिनके प्रश्न तर्क से उपजते थे और उत्तर अनुभूति से। दक्षिणेश्वर काली मंदिर विवेकानंद के जीवन का निर्णायक पड़ाव है। रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया प्रश्न- 'क्या आपने ईश्वर को देखा है?' और फिर मिले सीधे, निर्भीक उत्तर ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पंचवटी और नहावटखाना आज भी उस क्षण के साक्षी हैं, जब संशय ने सत्य का हाथ थामा। यहीं से विवेकानंद का धर्म अंधविश्वास नहीं, अनुभव और विवेक का पर्याय बन गया। काशीपुर उद्यानबाटी और वराहनगर मठ विवेकानंद के जीवन के सबसे कठोर, पर निर्णायक अध्याय हैं। काशीपुर में गुरु-सान्निध्य ने उन्हें संकेत दिया-'तुम्हारा काम बहुत बड़ा है।' यहीं से लोक-जागरण का बीज पड़ा। गुरु के महाप्रयाण के बाद वराहनगर के जर्जर मकान में कठोर साधना के बीच रामकृष्ण मिशन का अंकुर फूटा। यह स्थल सिखाता है कि महान संस्थाएं सुविधाओं से नहीं, संकल्प से खड़ी होती हैं। बागबाजार की गलियों में विवेकानंद को 'दरिद्र-नारायण' के दर्शन हुए। यहीं सेवा उनके दर्शन की धुरी बनी-'मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की पूजा है।' यही करुणा उन्हें हिमालय की कंदराओं और फिर पश्चिम के मंचों तक ले गई।

बेलूर मठ : यहीं बीते जीवन के अंतिम दिन

बेलूर मठ, जहां स्वामी ने महासमाधि ली।

हुगली तट पर स्थित बेलूर मठ विवेकानंद के विचारों का स्थापत्य रूप है। इसके मंदिर में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और इस्लामी तत्वों का समन्वय उनके 'सर्वधर्म समभाव' की मौन घोषणा करता है। यहीं उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली-मानो गंगा की धारा में विलीन होकर भी अनंत काल तक मार्गदर्शक बने रहना चाहते हों।

काशी : इसी नगरी ने स्वामी के भारत बोध को दी धार

आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में लक्सा स्थित रामकृष्ण मिशन ● जागरण

विवेकानंद के लिए काशी केवल धार्मिक नगर नहीं, बल्कि भारत का आत्मा था। 1887 से 1902 तक के प्रवासों में काशी ने उनके भारत बोध को धार दी। यहीं शिकागो जाने का संकल्प आकार लेता है- 'आदर्श की प्राप्ति करूंगा, नहीं तो देह त्याग दूंगा।' दुर्गाकुंड के जंगलों में बंदरों की घटना- 'रुको, सामना करो'— विवेकानंद का जीवन-सूत्र बन जाती है। काशी में प्रेरित युवाओं द्वारा शुरू 'होम आफ सर्विस' आज भी मानव-सेवा की जीवंत मिसाल है ।

कश्मीर : धरती पर स्वर्ग

स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी यात्राओं का वर्णन कश्मीर के बिना अधूरा है। सिस्टर निवेदिता से उन्होंने कहा था कि कश्मीर के सिवा किसी और जगह को छोड़ने का उन्हें दुख नहीं हुआ। इस धरती पर यह स्वर्ग है।

अल्मोड़ा : विचारों की साधना

सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण धर्म, अध्यात्म, कला, साहित्य और संगीत के जिज्ञासुओं को आकर्षित करता रहा है। वर्ष 1890 में पहली बार अल्मोड़ा आगमन के साथ ही स्वामी विवेकानंद का इस नगर से गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन गया। उन्होंने 1890, 1897 और 1898 में यहां की यात्राएं कीं। यह उनके विचारों की साधना का केंद्र रहा है। हिमालयी अल्मोड़ा विवेकानंद की साधना और सृजन का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। 12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेन्द्रनाथ की मृत्यु चार जुलाई 1902 को हो गई थी।

कोलकाता से **जयकृष्ण वाजपेयी**, वाराणसी से **शैलेश अस्थाना**, श्रीनगर से **नवीन नवाज** और अल्मोड़ा से **चंद्रशेखर द्विवेदी** की रिपोर्ट।

स्वामी विवेकानंद को 163वीं जयंती पर नमन

युवा शक्ति का वैचारिक मैनीफेस्टो

भारत की 65 प्रतिशत युवा आबादी के लिए स्वामी विवेकानंद केवल एक संन्यासी नहीं, बल्कि 'सफलता के वैज्ञानिक' हैं. 1985 से निरंतर उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला 'राष्ट्रीय युवा दिवस' इस वर्ष 'विकसित भारत@2047 : युवाओं की भूमिका' थीम पर केंद्रित है. यह दिन स्वामी जी के उन सूत्रों को पुनर्जीवित करने का अवसर है, जो आज की 'डिजिटल पीढ़ी' के मानसिक और व्यावहारिक भटकाव का एकमात्र समाधान हैं.

1 खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है.
-शिकागो व्याख्यान के बाद, 1893
सीख : मानसिक स्वास्थ्य और हीन भावना की चुनौती झेल रहे युवाओं के लिए यह आत्म-सम्मान की संजीवनी है.

2 पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए अनिवार्य हैं.
-शिष्य अलासिंगा पेरुमल को पत्र, 1894
सीख : 'तुरंत फल पाने की इच्छा' के दौर में यह सिखाता है कि महान उपलब्धियां चरित्र की शुद्धता और निरंतरता से ही संभव हैं.

3 उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए.
-कोलंबो से अल्मोड़ा व्याख्यान, 1897
सीख : 'टालमटोल' और 'डिस्ट्रैक्शन' के विरुद्ध महामंत्र, जो युवाओं को शॉर्ट-कट के बजाय दीर्घकालिक विजन की प्रेरणा देता है.

4 जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी.
-बेलूर मठ में शिष्यों से संवाद, 1901
सीख : विफलताओं से टूटने वाली पीढ़ी के लिए यह संघर्ष को व्यक्तित्व निखारने के एक अनिवार्य अवसर के रूप में परिभाषित करता है.

5 आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं.
-प्रसिद्ध व्याख्यान द रियल एंड द अपेरेंट मैन से
सीख : यह सकारात्मक दृष्टिकोण का आधार है. युवा अपने विचारों को ऊंचा रखकर ही महान व्यक्तित्व और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं.

'ग्रोक' से अश्लील सामग्री तैयार करने का मामले में 'एक्स' ने गलती स्वीकार की

छह सौ से ज्यादा खाते हटाए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जनवरी।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच 'एक्स' को 'ग्रोक एआइ' के अश्लील सामग्री मुद्दे पर चेतावनी दिए जाने के बाद माइक्रोब्लागिंग साइट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि लगभग 3,500 सामग्री 'अवरुद्ध' की गई हैं और 600 से अधिक खाते हटा दिए गए हैं।

यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब 'ग्रोक' पर दुनिया भर की सरकारों का दबाव बढ़ता जा रहा है। नियामक हाल के दिनों में 'एक्स' पर बड़ी संख्या में सामने आई आपत्तिजनक और बिना सहमति वाली यौन सामग्री और डेटा सुरक्षा को लेकर जेनरेटिव एआइ इंजन की कड़ी जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, 'एक्स' ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। साथ ही यह भी कहा है कि भविष्य में यह मंच अश्लील चित्रों की अनुमति नहीं देगा।

सरकार ने 'एक्स' से कहा कि लागू कानूनों का उल्लंघन करने वाली सभी पहले से बनाई या फैलाई गई सामग्री को 'बिना देरी' हटा दिया जाए या उसकी पहुंच बंद कर दी जाए। यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है, जब 'ग्रोक' पर दुनिया भर की सरकारों का दबाव बढ़ता जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, 'एक्स' ने कहा है कि भविष्य में यह मंच अश्लील चित्रों की अनुमति नहीं देगा। इस मुद्दे पर 'एक्स' और 'ग्रोक' दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सार्वजनिक मांग भी लगातार तेज हो रही है।

इस सोशल मीडिया मंच के 'सेफ्टी' हैंडल ने पिछले रविवार को कहा कि वह अपने मंच पर अवैध सामग्री, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री भी शामिल है, के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके तहत ऐसी सामग्री को हटाना, खातों को स्थायी रूप से निलंबित करना और आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारों एवं कानून प्रवर्तन एजंसियों के साथ काम करना शामिल है। 'एक्स' ने कहा था कि ग्रोक का उपयोग करके या उससे अवैध सामग्री बनवाने वाले किसी भी व्यक्ति को वही परिणाम भुगतने होंगे जो कि अवैध सामग्री अपलोड करने पर भुगतने पड़ते हैं। 'एक्स' एआइ चैटबाट 'ग्रोक' पर अश्लील तस्वीरों को लेकर 'एक्स' को वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप और एशिया समेत दुनिया भर की सरकारों ने आनलाइन सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं, इस मुद्दे पर 'एक्स' और 'ग्रोक' दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सार्वजनिक मांग भी लगातार तेज हो रही है। दो जनवरी को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'ग्रोक' व इस तरह की एआइ-आधारित सेवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से उत्पन्न की जा रही अश्लील और यौन सामग्री के संबंध में 'एक्स' को कड़ी चेतावनी जारी की थी।

इस निर्देश में मंत्रालय ने अमेरिका स्थित सोशल मीडिया कंपनी से 72 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रपट प्रस्तुत करने को कहा। इसमें ग्रोक एप से जुड़े अब तक किए गए या प्रस्तावित तकनीकी और संगठनात्मक कदमों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और निगरानी, आपत्तिजनक कंटेंट, उपयोक्ताओं और खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई, साथ ही भारतीय कानूनों के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था का विवरण देने को कहा गया। आइटी मंत्रालय के पत्र में कहा गया कि 'एक्स' द्वारा विकसित और मंच पर एकीकृत 'ग्रोक एआइ' का कुछ उपयोगकर्ता दुरुपयोग कर रहे हैं।

Jansatta Page

पीएसयू का निजीकरण कर संसाधन जुटाए सरकार

सीआइआइ ने बजट पूर्व सुझाव में कहा-इससे पूंजीगत खर्च और विकास संबंधी योजनाओं को पूरा करने में मिलेगी मदद

बजट 2026-27

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट के लिए सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) निजीकरण करके संसाधन जुटाने चाहिए। इसके लिए ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी से दक्षता बढ़े, नई प्रौद्योगिकी आए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत हो। इससे पूंजीगत खर्च और विकास संबंधी जरूरी योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सीआइआइ ने केंद्र से तीन साल की अवधि के लिए निजीकरण योजना का एलान करने का आह्वान किया है, जिसमें यह बताया जाए कि इस अवधि में किन उद्यमों का निजीकरण किया जा सकता है। इसमें तर्क दिया गया कि इससे निवेशकों की गहरी भागीदारी और अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहन मिलेगा, जो निजीकरण की प्रक्रिया की तेजी में योगदान देगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी को शुरू में 51 प्रतिशत तक कम कर सकती है, जिससे वह सबसे बड़ी एकल शेयरधारक बनी रहेगी और बाजार में महत्वपूर्ण मूल्य का प्रवाह होगा। समय के साथ, इस हिस्सेदारी को और कम करके 33 से 26 प्रतिशत के बीच लाया जा सकता है। सीआइआइ के विश्लेषण के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 78 सूचीबद्ध उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत करने से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

- उद्योग संगठन ने केंद्र से तीन साल की अवधि के दौरान निजीकरण करने की योजना का एलान करने का आह्वान किया
- सरकार चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी शुरू में 51 प्रतिशत तक कम करे

75% से कम हिस्सेदारी वाले उद्यमों का पहले विनिवेश हो

रोडमैप के पहले दो सालों के दौरान 55 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश किया जाए, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत या उससे कम है। इन उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने से 4.6 लाख करोड़ रुपये एकत्र होंगे। अगले चरण में 75 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी हिस्सेदारी वाले 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश किया जा सकता है, जिससे 5.4 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनने में मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए उद्योग संगठन सीआइआइ ने कहा कि अभी सरकार बिक्री के लिए किसी खास उद्यम की पहचना करती है और बाद में निवेशकों को बुलाती है। हालांकि, जब वैल्यूएशन नहीं मिलता है तो विनिवेश की प्रक्रिया रुक जाती है।

सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी को सोच-समझकर 51 प्रतिशत या उससे भी कम करना एक व्यावहारिक कदम होगा और यह रणनीतिक नियंत्रण और मूल्य सृजन के बीच संतुलन बनाता है। विनिवेश से मिलने वाली लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी सामाजिक ढांचे के विकास को तेज करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी।
-**चंद्रजीत बनर्जी**, महानिदेशक, सीआइआइ

बजट में सुपर-रिच पर आयकर सरचार्ज बढ़ाने से बचे सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार को आगामी बजट में सुपर रिच लोगों पर आयकर सरचार्ज बढ़ाने और वेल्थ टैक्स को फिर से लागू करने से बचना चाहिए। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ज्यादा आय वाले लोग देश छोड़कर कम टैक्स वाले इलाकों में जा सकते हैं।

अभी, 50 लाख रुपये से ज्यादा सालाना कमाई करने वाले लोगों को आयकर पर सरचार्ज देना पड़ता है। 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच की आय पर 10 परसेंट, 1-2 करोड़ रुपये पर 15 परसेंट और 2-5 करोड़ रुपये पर 25 परसेंट सरचार्ज लगता है। जो लोग पांच करोड़ रुपये से ज्यादा कमाते हैं और नए इनकम टैक्स सिस्टम में हैं, उन्हें 25 परसेंट सरचार्ज देना होगा, जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में आने वालों को 37 परसेंट की दर से सरचार्ज देना होगा।

अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक, जीएसटी दरों को कम करने और इनकम टैक्स में राहत देने से चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग दो लाख करोड़ रुपये का भार पड़ने की संभावना है। आगामी बजट में कोई भी नया कर सरकार को रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में अतिरिक्ति आवंटन में मदद कर सकता है।

INTERNATIONAL

जर्मनी के चांसलर की दो दिनी भारत यात्रा आज से

भारत-जर्मनी रिश्तों को नये आयाम देंगे मोदी और मर्ज

- रक्षा से ग्रीन हाइड्रोजन तक समझौते के आसार
- मर्ज की जर्मन चांसलर बनने के बाद यह पहली एशिया यात्रा

एजेंसियां, नयी दिल्ली

वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भारत और जर्मनी अपने रणनीतिक रिश्तों को नयी ऊंचाई देने की तैयारी में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज सोमवार को अहमदाबाद में व्यापक वार्ता करेंगे. बातचीत का फोकस व्यापार, निवेश, रक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर रहेगा. 12–13 जनवरी की यह यात्रा चांसलर बनने के बाद फ्रेडरिक मर्ज की पहली एशिया यात्रा है, जिसे बर्लिन और नयी दिल्ली दोनों के लिए खास माना जा रहा है. अमेरिका-वेनेजुएला तनाव, यूक्रेन युद्ध और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच यह मुलाकात अहम मानी जा रही है. सूत्रों के अनुसार यूक्रेन में शांति की संभावनाओं पर भी चर्चा संभव है. आर्थिक मोर्चे पर रिश्ते मजबूत हुए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-जर्मनी सेवा व्यापार 12.5 प्रतिशत बढ़ कर रिकॉर्ड 16.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

साबरमती आश्रम भी जायेंगे पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के अलावा फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम जायेंगे, जहां पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे और स्किल डेवलपमेंट इवेंट में शामिल होंगे. अहमदाबाद के कार्यक्रमों के बाद मर्ज बेंगलुरु का दौरा करेंगे.

भारत-जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे

भारत और जर्मनी ने वर्ष 2000 में 21वीं सदी के लिए रणनीतिक एजेंडा तय किया था. पिछले साल यह रणनीतिक साझेदारी 25 साल पूरी कर चुकी है. मौजूदा हालात में यह यात्रा और बातचीत दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.

क्यों अहम है यह यात्रा

यूरोप के साथ आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने की रणनीति

बैठक में व्यापार और निवेश पर खास जोर रहेगा. अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाये जाने के बाद भारत यूरोप के साथ आर्थिक साझेदारी को और गहरा करना चाहता है. इसी सिलसिले में जर्मनी के साथ आर्थिक सहयोग को रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. जर्मनी, यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वर्ष 2024-25 में भारत-जर्मनी के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 51.23 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह भारत के कुल इयू व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत है.

वार्ता में इन पर रहेगी नजर

डिफेंस डील : रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का अहम हिस्सा होगा. मर्ज की इस यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच छह स्टेल्थ सबमरीन की आपूर्ति को लेकर अंतर-सरकारी समझौता अंतिम रूप ले सकता है.

समुद्री सुरक्षा और तकनीक : भारत और जर्मनी के बीच आतंकवाद पर संयुक्त कार्य समूह पहले से सक्रिय है. जर्मनी, भारत के इंटीग्रेटेड फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन में अपना नौसेना संपर्क अधिकारी तैनात करने जा रहा है. शिक्षा, ऊर्जा, कौशल विकास, संस्कृति, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी संबंध मजबूत होंगे.

ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य की तकनीक : 2024 में दोनों देशों ने इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप लॉन्च किया था. इसे आगे लेकर जाना है. क्रिटिकल और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर रहेगा.

वेनेजुएला के सैनिक करने लगे थे खून की उल्टी, नाक से बहने लगा खून

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क

- रहस्यमय हथियार से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के सैनिकों पर बोला हमला
- सभी जमीन पर गिर पड़े, न वे हिल पा रहे थे, न ही खड़े हो पा रहे थे

तीन जनवरी को अमेरिकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास के सैन्य परिसर में लगी आग। फाइल

अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में की गई कार्रवाई के संबंध में सामने आ रही जानकारी बेहद चौंकाने और डराने वाली हैं। न्यूयार्क पोस्ट के अनुसार, निकोलस मादुरो को पकड़ने पहुंची अमेरिका सेना ने एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए। उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे। इससे पहले भी चीन पर 2020 में लद्दाख में सीमा विवाद के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, हालांकि बीजिंग ने इन दावों का खंडन किया था।

एक साक्षात्कार में, गार्ड ने बताया कि कैसे अमेरिकी सेना ने सैकड़ों लड़ाकों को बिना एक भी सैनिक खोए मार गिराया। उसने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल न तो पहले कभी देखा न सुना था। गार्ड ने कहा, "हम सतर्क थे, अचानक हमारे सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। फिर बहुत सारे ड्रोन नजर आने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।" कुछ क्षणों बाद हेलीकाप्टर दिखाई दिया। वे मुश्किल से आठ थे। करीब 20 सैनिक उतरे। वे उन दुश्मनों से बिल्कुल अलग थे, जिनसे हमने पहले कभी लड़ाई लड़ी थी। वह लड़ाई नहीं, बल्कि नरसंहार था। गार्ड ने कहा, "हम सैकड़ों थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वे इतनी सटीकता और गति से गोलियां चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हर सैनिक एक मिनट में 300 गोलियां दाग रहा हो।" फिर वह हथियार आया जिसे सोचकर सिहर जाते हैं। उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह बहुत तीव्र ध्वनि तरंग थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सिर अंदर से फट रहा हो।" उसका असर भयावह था। सभी की नाक से खून बहने लगा। कुछ खून की उल्टी कर रहे थे। हम जमीन पर गिर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके इस्तेमाल के बाद हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।"

व्हाइट हाउस के प्रेस मंत्री ने शनिवार को एक्स पर प्रत्यक्षदर्शी का बयान पोस्ट किया। इस सवाल पर व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया कि क्या कैरोलिन लेविट द्वारा पोस्ट साझा करने से यह संकेत मिलता है कि प्रशासन प्रत्यक्षदर्शी के बयान की सत्यता की पुष्टि कर रहा है।

इस बारे में एक पूर्व अमेरिकी खुफिया सूत्र ने न्यूयार्क पोस्ट को बताया कि अमेरिकी सेना के पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपंस कई वर्षों से मौजूद हैं, जो माइक्रोवेव या लेजर बीम जैसी केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्यों को निष्क्रिय कर देते हैं।

हालांकि, यह पहली बार हो सकता है जब अमेरिका द्वारा इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया हो।

वेनेजुएला में कैदियों की रिहाई जारी

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, वेनेजुएला में कैदियों की रिहाई तीसरे दिन भी जारी रही। सरकार ने सद्भावना प्रयासों की घोषणा की है। डायोजेन्स एंगुलो को शनिवार को एक साल और पांच महीने बाद जेल से रिहा किया गया। एंगुलो को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से दो दिन पहले उस समय हिरासत में लिया गया था जब उन्होंने दिवंगत राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के गृह राज्य बारिनास में विपक्षी प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट किया था। इससे पहले नौ लोगों को जेल से किया गया था।

मादुरो का अमेरिकी जेल से बेटे को संदेश, 'हम ठीक हैं, मैं एक योद्धा हूं'

आइएएनएस के अनुसार, वेनेजुएला के सांसद निकोलस मादुरो गुएरा ने कहा कि उनके पिता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने वकीलों के माध्यम से संदेश भेजा है कि वे ठीक हैं। अमेरिका में हिरासत में रहते हुए भी वे दृढ़ संकल्पित हैं। गुएरा ने कहा, "वे मजबूत हैं और हमें दुखी नहीं होना चाहिए।" उन्होंने कहा है, "हम ठीक हैं। मैं एक योद्धा हूं।"====

तनातनी के बीच ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका

बढ़ेगा संकट ▸ ट्रंप को दी गई हमलों के नए विकल्पों की जानकारी, कल फिर होगी बैठक

न्यूयार्क टाइम्स से

- ट्रंप बोले, ईरान ने कार्रवाई की तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को तैयार
- रिपब्लिकन सीनेटर ने कहा, अमेरिका मुर्दाबाद कहने वालों को जल्द मिलें 72 हूरें

मैरीलैंड में एयर फोर्स वन पर सवार होने के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर >>

वाशिंगटन : वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर लाने की सफलता से उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप को हाल के दिनों में ईरान पर सैन्य हमलों के नए विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है। मंगलवार को भी ट्रंप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार है। उनकी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया में उनकी पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज ने शनिवार को कहा, 'काश अमेरिका मुर्दाबाद कहने वालों को आज रात ही उनकी 72 हूरें मिल जाएं।'

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन वह प्रदर्शनों को दबाने के ईरानी सरकार की कोशिशों के जवाब में हमले को मंजूरी देने पर गंभीरता से विचार कर रहे। राष्ट्रपति को कई विकल्प दिए गए हैं, जिसमें राजधानी तेहरान में असैन्य ठिकानों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रंप को दिए गए कुछ विकल्प सीधे तौर पर ईरान की सुरक्षा सेवाओं के उन तत्वों से जुड़े हुए हैं, जो बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी सैन्य हमले का उलटा असर न हो, जैसे- ईरानी जनता सरकार के समर्थन में एकजुट न हो जाए या जवाबी हमलों की एक ऐसी श्रृंखला न शुरू हो जाए जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य और राजनयिक कर्मियों के लिए खतरा बन जाए। एक अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र के कमांडर किसी भी संभावित हमले से पहले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मजबूत करने और ईरान के किसी संभावित जवाब की तैयारी के लिए और समय चाहेंगे। किसी भी सैन्य कार्रवाई में इस बात का संतुलन बनाना होगा कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है तो ट्रंप के वादे को कैसे पूरा किया जाए और स्थिति भी और खराब न हो।

संभावित हमलों की योजना के बारे में व्हाइट हाउस ने ट्रंप की हालिया सार्वजनिक टिप्पणियों और इंटरनेट मीडिया पोस्ट का हवाला दिया। ट्रंप ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर लिखा, 'ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जैसा उसने शायद पहले कभी नहीं किया। अमेरिका मदद के लिए तैयार है!!!' उनकी इस पोस्ट के जवाब में रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि अगर ईरानी लोग अयातुल्ला अली खामेनेई को हटा देते हैं, तो अमेरिका और पूरी दुनिया बहुत अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

गौरतलब है कि मुद्रा संकट के जवाब में ईरान में दिसंबर के आखिर में प्रदर्शन शुरू हुए थे। अब ये बड़े पैमाने पर फैल गए हैं। कई ईरानियों ने देश की अधिनायकवादी सरकार में बड़े बदलावों की मांग की है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने शुक्रवार को कहा था कि सरकार विरोध प्रदर्शनों के कारण पीछे नहीं हटेगी। वहीं, ट्रंप ने ईरानी सरकार के प्रयासों के विरुद्ध बार-बार बल प्रयोग की धमकी दी है। शुक्रवार को उन्होंने कहा था, ईरान बड़ी मुसीबत में है। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करेंगे तो हम दखल देंगे। वेनेजुएला की सफलता से बेलगाम हो चुके ट्रंप का कहना था, 'हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब जमीन पर सेना उतारना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसा करना पड़े।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की नेतन्याहू से बात

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों व अमेरिकी दखल के साथ-साथ सीरिया की स्थिति और गाजा पट्टी में शांति समझौते पर चर्चा की। रूबियो ने अपने निजी इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा, 'अमेरिका ईरान के साहसी लोगों का समर्थन करता है।'

इजरायल में हाई अलर्ट

रायटर के अनुसार, ईरान में किसी भी अमेरिकी दखल की संभावना को लेकर इजरायल हाई अलर्ट पर है। सूत्रों ने हालांकि यह नहीं बताया कि व्यावहारिक तौर पर इजरायल में हाई अलर्ट का क्या मतलब है। कट्टर दुश्मन होने के बावजूद इजरायल ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में दखल देने की किसी इच्छा का संकेत नहीं दिया है। शुक्रवार को एक साक्षात्कार में नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो इसके भयानक परिणाम होंगे। विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उनका कहना था, 'मुझे लगता है कि हमें नजर रखनी चाहिए कि ईरान में क्या हो रहा है।'

... तो इजरायल के साथ अमेरिकी अड्डों को भी कर देंगे बर्बाद : ईरान

मोहम्मद बाकर कलीबाफ। वीडियोग्रैब/रायटर

तेहरान, रायटर : ईरान ने रविवार को धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह इजरायल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के एलीट रिवोल्यूशनरी गाड्र्स के पूर्व कमांडर और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने रविवार को संसद में यह चेतावनी तब दी जब ईरानी सांसद 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे। कलीबाफ ने कहा, 'अगर ईरान पर हमला हुआ तो कब्जे वाले इलाके (इजरायल) के साथ-साथ सभी अमेरिकी अड्डे और पोत हमारे निशाने पर होंगे।' ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलान किया है कि अगर ईरानी सरकार ने ऐसा या वैसा किया, तो वह प्रदर्शनकारियों का साथ देंगे। प्रदर्शनकारियों ने उन से उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर वह इतने काबिल हैं, तो पहले अपने देश को संभाल लें।'

ईरान में सरकार के बल प्रयोग से बेकाबू हुए हालात

तेहरान : ईरान में दो हफ्ते से जारी महंगाई के विरोध वाले आंदोलन में शनिवार-रविवार को हालात और बेकाबू हो गए। तेहरान सहित 100 से ज्यादा शहरों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों के साथ टकराव में अभी तक 538 लोग मारे गए हैं। (पेज-11)

Dainik Jagaran

मचाडो के सुझाव पर नोबेल संस्थान ने कहा, पुरस्कार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता

न्यूयार्क टाइम्स से

नोबेल पुरस्कार। फाइल

न्यूयार्क : नार्वेजियन नोबेल संस्थान ने कहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार को हस्तांतरित, साझा या रद नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो द्वारा दिए गए उस सुझाव के बाद आई है जिसमें उन्होंने अपना 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देने की पेशकश की थी।

नोबेल फाउंडेशन के नियमों का हवाला देते हुए बयान में संस्थान ने कहा कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद नहीं किया जा सकता, न ही इसे साझा किया जा सकता है और न ही किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय अंतिम और स्थायी होता है। इसमें अपील की अनुमति नहीं है। संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि पुरस्कार देने वाली समितियां पुरस्कार विजेताओं के कार्यों या बयानों पर टिप्पणी नहीं करती हैं। सोमवार को मचाडो ने फाक्स न्यूज पर बातचीत के दौरान कहा था कि ट्रंप को पुरस्कार देना निकोलस मादुरो, जोकि देश के राष्ट्रपति हैं, को हटाने के लिए वेनेजुएला के लोगों की तरफ से आभार का काम होगा। मादुरो को पिछले सप्ताह अमेरिका ने वेनेजुएला से सपत्नी पकड़ा था। बता दें कि ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए आतुर हैं। मचाडो का यह सुझाव और नोबेल संस्थान की प्रतिक्रिया, दोनों ही वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गए हैं। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे पुरस्कारों का राजनीतिकरण किया जा सकता है।

यूरोपीय यूनियन में भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य बनकर उभरे स्पेन, जर्मनी व पोलैंड

- अप्रैल से नवंबर के दौरान स्पेन को निर्यात 56 प्रतिशत बढ़कर 4.7 अरब डालर हुआ
- चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में जर्मनी को निर्यात 9.3% बढ़ 7.5 अरब डालर रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: यूरोपीय यूनियन (ईयू) में स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड भारत के प्रमुख निर्यात गंतव्य बनकर उभर रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि स्पेन भारतीय निर्यात के लिए एक उच्च वृद्धि बाजार के तौर पर अलग दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान स्पेन को निर्यात 56 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 4.7 अरब डालर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में तीन अरब डालर था। भारत के कुल निर्यात में स्पेन की हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2.4 प्रतिशत हो गई है।

इसी तरह, चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में जर्मनी को भारत का निर्यात 6.8 अरब डालर से 9.3 प्रतिशत बढ़कर 7.5 अरब डालर हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि कुल निर्यात में 2.6 प्रतिशत हिस्सेदारी और 0.2 प्रतिशत की सकारात्मक हिस्सेदारी बढ़त के साथ जर्मनी भारतीय उत्पादों के लिए लगातार स्थिर मांग पैदा कर रहा है। अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान बेल्जियम को निर्यात 4.2 अरब डालर से बढ़कर 4.4 अरब डालर हो गया। अप्रैल-नवंबर 2024 में पोलैंड को निर्यात 1.69 अरब डालर से 7.6% बढ़कर 1.82 अरब डालर हो गया। भारत और ईयू के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत के कुल निर्यात में ईयू की हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है और भारत को होने वाला निर्यात, उसके कुल विदेशी निर्यात का नौ प्रतिशत है।

EDITORIAL

इंसानियत की संवेदना

राजेंद्र वामन काटदरे

पिछले कुछ समय से समाज में आसपास होती घटनाएं इस मसले पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिस संवेदना की बुनियाद पर इंसानियत टिकी हुई है, उसकी जगह क्यों सिकुड़ती जा रही है। आजकल की खबरों को देखकर मन में एक ही भाव जागता है कि क्या मनुष्य अपनी संवेदना खोता जा रहा है और क्या हमारे दिलोदिमाग से संवेदनशीलता का ह्रास हो रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें यह देखा गया कि किसी दुर्घटना के बाद घायल लोगों की मदद करने की जगह घटनास्थल पर मौजूद लोग अपने-अपने मोबाइल निकाल कर घटना का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए लोग क्या एक बार भी नहीं सोचते कि हादसे के बाद घायल व्यक्ति के लिए एक-एक पल कितना कीमती होता है। यह सोचने के बजाय वीडियो बनाना या मूकदर्शक होकर देखते रहने वालों की भीड़ में दिमागी तौर पर लोगों का अनुपस्थित होना संवेदनहीनता नहीं, तो और क्या है।

सच तो यह है कि मनुष्य का दिल या कहें कि मानव मन अनेक प्रकार की भावनाएं, एहसास, बोध, चेतना, सहानुभूति, हमदर्दी, वेदना आदि समेटे हुए होता है। इसलिए हमारी आंखों के सामने घटित होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद सर्वप्रथम हमारे मन में घायल लोगों की मदद करने का भाव जागना चाहिए, मगर वर्तमान में संवेदनशीलता खोता आदमी या तो अपने मोबाइल में घटना का वीडियो बनाना शुरू कर देता है या किसी एक अनजान भय से घटनास्थल से पलायन ही कर जाता है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति अपनी ही संवेदना खो चुका होता है या फिर उस पर प्रचार की भूख हावी होती है और दूसरी ओर अनजान भय से घटनास्थल से पलायन करने वाला व्यक्ति कानूनी जटिलताओं में फंसने से लेकर मदद करने के क्रम में वक्त 'जाया होने' के डर से ऐसा करता है। फिर कई बार किसी व्यक्ति की प्रकृति ही मदद न करने या फिर मुश्किल में मदद न करने वाले की होती है।

हालत यह है कि अगर किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद करने की जरूरत होती है और कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा होता है, तो भी पास से गुजर रहे वाहन रुकते नहीं। दस मिनट में पिज्जा पहुंचाने वाले शहरों में भी एंबुलेंस घंटे भर के इंतजार के बाद ही पहुंचती है। इतनी देर में कई बार मरीज की जान पर बन आती है या उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद न करने के अनेक बहाने हम अपने मन में झटपट गढ़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कि अब पुलिस के झंझट में कौन पड़े... या इसके बाद कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कई बार तो किसी बैठक में हिस्सा न ले पाने या या हवाई जहाज के छूट जाने का बहाना हमारा मन सोच लेता है। दरअसल, इसे बहाना ही कहा जा सकता है, क्योंकि क्या किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा कीमत किसी बैठक की या हवाई जहाज के छूट जाने से की जा सकती है?

अस्पतालों में भी संवेदनाओं का अभाव के मामले आम दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर मरीजों के इलाज के लिए फार्म या पर्ची भरे बगैर या पैसा जमा किए बगैर या फिर पुलिस के आने से पहले मरीज का इलाज नहीं किया जाता, भले ही मरीज गंभीर अवस्था में हो और उसे आपात चिकित्सा की जरूरत है। संवेदनहीनता तब भी दिखाई देती है जब किसी परिचित या दूर के किसी रिश्तेदार के घर में हुई गमी यानी किसी की मौत के बाद लोग दुख में शामिल होने उनके घर पहुंचने के बजाय अपने मोबाइल पर 'रेस्ट इन पीस' या 'विनम्र श्रद्धांजलि' लिख कर अपने कर्तव्य की ईतिश्री मान लेते हैं। सोच कर देखा जा सकता है कि क्या किसी गमजदा व्यक्ति के मोबाइल में आया संदेश सकी मानसिक-भावनात्मक मदद करेगा या उसके कंधे पर किसी अपने का आश्वासन देने वाले हाथ उसे ज्यादा अच्छे लगेंगे।

दुनिया मेरे आगे

> अगर दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद की जरूरत होती है और कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा होता है, तो भी पास से गुजर रहे वाहन रुकते नहीं। दस मिनट में पिज्जा पहुंचाने वाले शहरों में भी एंबुलेंस घंटे भर के इंतजार के बाद ही पहुंचती है।

इसके विपरीत संवेदनहीनता के इस वर्तमान समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो मदद के लिए दौड़ पडते हैं। हम सबने सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे समूह देखे होंगे, जो गुड मार्निंग, गुड नाइट के साथ दिनभर लतीफे तथा मीम या मनोरंजक रील एक-दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर कुछ समूह ऐसे भी हैं, जो सिर्फ मदद करने के उद्देश्य से बने हैं। रक्त दान करने वालों का एक समूह ऐसा भी है जो देश भर के अस्पतालों में अपने नेटवर्क के जरिए जरूरतमंदों को खून देने पहुंच जाते हैं।

कुछ समय पहले एक नन्हे बालक के हृदय में छेद था, जिसका आपरेशन करवाना जरूरी था। साथ ही खर्च बहुत था, जिसे उसके माता-पिता उठाने में सक्षम नहीं थे। मगर सोशल मीडिया पर किसी भले मानुष ने इस संबंध में लिख कर जारी किया। इसके बाद मदद के लिए अनेक हाथ उठे और उससे नन्हे बच्चे का आपरेशन एक बड़े अस्पताल में बिना दिक्कत हो गया। बचे हुए पैसों से बैंक में एक एफडी बनवाई गई, जिससे भविष्य में उसके शिक्षण में भी मदद हो सके। एक तरफ कुछ अस्पताल सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, तो कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं, जो पैसों से ज्यादा मनुष्यों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मनुष्यता की फिक्र करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के लोग इस देश-दुनिया में हैं। न तो संवेदनशीलता कम हुई है, न सभी मनुष्य संवेदनहीन हो गए हैं।

टीबी से मुक्ति की राह में अड़चन

देवेंद्रराज सुथार

दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में शामिल आज भी भारत के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में भले ही धीरे-धीरे कमी आ रही हो, लेकिन कुल मामलों का लगभग एक चौथाई हिस्सा अब भी केवल भारत में दर्ज किया जाता है। भारत सरकार ने पहले 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत में 2015 के बाद से टीबी के नए मामलों में 21 प्रतिशत और इस बीमारी से होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत की कमी आई है। यह प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही चिंताजनक है। वर्ष 2024 में दुनिया भर में लगभग एक करोड़ सात लाख लोग टीबी से बीमार हुए, जिनमें बड़ी संख्या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की थी। इसी वर्ष वैश्विक स्तर पर टीबी से 12.3 लाख मौतें दर्ज हुईं, जिनमें से लगभग तीन लाख मौतें केवल भारत में हुईं।

> भारत सरकार ने पहले 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है

टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, फिर भी यह बड़े पैमाने पर जानलेवा बनी हुई है। यह बीमारी बैक्टीरिया से होती है और मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। हवा के जरिये फैलने वाली इस बीमारी का संबंध केवल चिकित्सा व्यवस्था से नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी है। भारत में टीबी के अधिक मामलों के पीछे स्वास्थ्य पर कम सरकारी खर्च भी एक अहम कारण माना जाता है। जहां वैश्विक स्तर पर औसतन देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग छह प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, वहीं भारत में यह खर्च लंबे समय से एक से डेढ़ प्रतिशत के बीच ही रहा है। सीमित संसाधनों के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, समय पर जांच और निरंतर इलाज कई क्षेत्रों में कमजोर पड़ जाती हैं, जिसका सीधा असर टीबी नियंत्रण पर पड़ता है।

भारत ने 2018 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वैश्विक लक्ष्य से पहले टीबी खत्म करने का संकल्प लिया था। इस दौरान जांच, इलाज और निगरानी से जुड़ी कई रणनीतियां अपनाई गईं। देश टीबी उन्मूलन के पूर्व चरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कई गरीब और पिछड़े जिले अब भी बड़ी बाधा बने हुए हैं। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इसे केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी न मानकर व्यापक सामाजिक चुनौती के रूप में देखा जाए। पोषण, गरीबी उन्मूलन, जागरूकता, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना टीबी को जड़ से खत्म करना संभव नहीं होगा। भारत के सामने यह चुनौती केवल आंकड़ों को सुधारने की नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों को सुरक्षित भविष्य देने की भी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खतरे में अमेरिकी साम्राज्य!

अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और समृद्ध देश है। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद करीब तीन दशक तक अमेरिका को वैश्विक मंच पर कोई खास चुनौती नहीं मिली और इसका मुख्य कारण उसकी मुद्रा डालर है। वैश्विक मोर्चे पर आर्थिक व्यवस्था में डालर का प्रभुत्व बना हुआ है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से वैश्विक मंचों पर चीन और भारत का उभार डालर के इस प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। एक तरफ चीन जहां तमाम देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। वहीं, भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों का संगठन ब्रिक्स डालर से इतर अपनी मुद्रा लाने पर विचार कर रहा है। इससे अमेरिका को डालर की बादशाहत खतरे में नजर आ रही है। यदि डालर का वैश्विक प्रभुत्व कमजोर होता है तो इससे अमेरिका का आर्थिक दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डी-डालराइजेशन के प्रयासों को बढ़ावा देने वाले देशों को टैरिफ समेत अन्य प्रकार की धमकी दे रहे हैं। इन देशों में रूस, चीन और भारत प्रमुख हैं। डी-डालराइजेशन के इस ट्रेंड पर अमेरिका की चिंता और इससे निपटने के लिए अपनाई जा रही है उसकी नीतियों की पड़ताल आज का अहम मुद्दा है...

डालर का विकल्प तलाश रही है दुनिया

डालर का दशकों से अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के तौर पर प्रभुत्व रहा है। हालांकि, अब चीजें बदल रही हैं। रूस, चीन और भारत सहित कई देश अमेरिका से निर्भरता कम करने और अमेरिकी प्रतिबंधों के असर से बचने के लिए अपनी मुद्रा में दूसरे देशों से व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। डालर के प्रभुत्व और डी- डालराइजेशन के मजबूत हो रहे ट्रेंड पर प्रकाश डाल रहे हैं **महेन्द्र सिंह-**

साझा मुद्रा पर विचार कर रहे ब्रिक्स देश

40% वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स

26% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी है ब्रिक्स के सदस्य देशों की

- डोनाल्ड ट्रंप डालर के प्रभुत्व को चुनौती देने की संभावना पर ब्रिक्स देशों को दे चुके हैं धमकी

- वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाह में दशकों से अमेरिकी डालर का प्रभुत्व रहा है
- बहुत से देश अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए डालर का विकल्प तलाश रहे हैं। वे अपनी मुद्रा में दूसरे देशों से व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं

क्या है डी- डालराइजेशन

डी-डालराइजेशन का मतलब है वैश्विक व्यापार, वित्त और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डालर के प्रभुत्व को कम करना। इसमें देश डालर के बजाय अन्य मुद्राओं जैसे- युआन, रूबल, रुपया, या सोने का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए मुद्रा के तौर पर डालर से अपनी निर्भरता घटाते हैं, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों और विदेश नीति के प्रभावों से बचा जा सके और अपनी आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाई जा सके।

डालर के प्रभुत्व का इतिहास

1920 का दशक
डालर ने अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा के तौर पर स्टर्लिंग और पाउंड की जगह लेनी शुरू की। विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा सोना आया

1944
ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार डालर में किया गया

1960 का दशक
यूरोप और जापान के उत्पाद निर्यात बाजार में अमेरिकी उत्पादों को कड़ी टक्कर देने लगे। दुनिया में डालर की आपूर्ति काफी अधिक हो गई। ऐसे में डालर को सोने का समर्थन देना मुश्किल हो गया

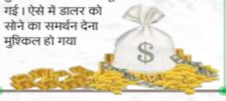

1971
अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डालर को सीधे सोने में बदलने पर रोक लगा दी

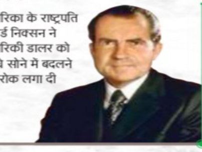

1981
वर्षों तक काफी अधिक महंगाई (हाइपर इन्फ्लेशन) के कारण डालर ने अपनी दो तिहाई खरीद क्षमता गवां दी

2007-2008
वैश्विक वित्तीय संकट: निवेशकों में डालर की मांग बढ़ी। उनको उम्मीद थी कि डालर अपनी वैल्यू बरकरार रखेगा

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला

303 अरब बैरल अनुमानित तेल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला के पास

10 अरब डालर का कर्ज है चीन का वेनेजुएला पर

- वेनेजुएला कर्ज के बदले चीन को तेल की कर रहा था आपूर्ति
- हमले के बाद अमेरिका के नियंत्रण में आ गया है वेनेजुएला का तेल कारोबार
- अमेरिका की कंपनियां बढ़ाएंगी वेनेजुएला में तेल उत्पादन
- तेल व्यापार पर अमेरिका के नियंत्रण से डालर में सुनिश्चित होगा ट्रांजैक्शन

2023
- ब्राजील और अर्जेंटीना ने साझा मुद्रा शुरू करने पर विचार-विमर्श किया
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और भारत ने तेल के अलावा दूसरी वस्तुओं का व्यापार रुपये में करने की संभावनाओं पर बातचीत शुरू की
- रूस- ईरान सोना समर्थित क्रिप्टोकरेंसी लाने पर पर काम कर रहे हैं
- रूस और भारत रुपये-रूबल में आपसी व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं
- 48 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब ने कहा है कि तेल निर्यातक देश डालर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी व्यापार कर सकते हैं

विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्राओं की हिस्सेदारी

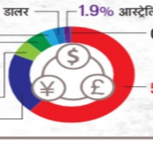

शुरू हुआ डी- डालराइजेशन

2022
- केंद्रीय बैंकों ने 1987 के बाद सबसे ज्यादा सोना खरीदा। दुनिया के तमाम देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डालर कम करते हुए विविधता लाना चाहते थे
- यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद रूस और चीन ने रूबल और युआन में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। रूबल-युआन व्यापार आठ महीनों में 80 गुना बढ़ गया

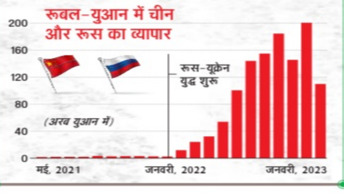

2014
क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के जवाब में डी-डालराइजेशन को प्राथमिकता दी। उसने दूसरे देशों के साथ रूबल में व्यापार शुरू किया

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, नयी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का युवाओं को संदेश

अगर आप शक्तिशाली हैं, तो आप स्वतंत्र रहेंगे

नेशनल कंटेंट सेल

दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को संदेश दिया. उन्होंने युवाओं को इतिहास से सीखने और एक मजबूत भारत के निर्माण का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा अंतर है. मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था, जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था. मैंने वो भारत देखा है जो बहुत गरीब था, जो बहुत लाचार था, जिसके पास भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं थीं. भारत विकसित होगा, यह निश्चित है. भारत ने कई सफलताएं देखी हैं. हम कभी विज्ञान, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के शिखर पर थे, लेकिन हमारा पतन हुआ क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है. यह एक निरंतर संघर्ष है. राष्ट्रवाद और स्वयं राष्ट्र को मजबूत बने रहने के लिए निरंतर कोशिश की जरूरत होती है और यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता. यह भारत वैसा स्वतंत्र नहीं था जैसा आप आज देखते हैं. हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, अपमान सहे और कई लोगों को फांसी दी गयी. भगत सिंह को फांसी दी गयी, सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर संघर्ष किया और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग प्रशस्त किया. अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवायी. भारत को आजादी बहुत मुश्किल से मिली है. आप इतिहास से प्रेरणा लें और अपने देश को फिर से मजबूत बनाएं. यह भारत अपने मूल्यों, अधिकारों और विश्वासों पर आधारित होना चाहिए. हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी. हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े. हम कहीं लूटने नहीं गये. अगर आने वाली पीढ़ियां इनको भूल गयीं, तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा. हम युद्ध क्यों लड़ते हैं? हम साइकोपैथ नहीं हैं, जिन्हें दुश्मन की लाशें, मरे हुए शरीर और कटे हुए अंग देखकर बहुत संतुष्टि या खुशी मिलती है. युद्ध इसलिए नहीं लड़े जाते. युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वह हमारी इच्छा के अनुसार सरेंडर कर दे. राष्ट्र की इच्छाशक्ति ही वह चीज है, जिसके लिए युद्ध लड़े जाते हैं. आज भी, जितने भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, उन्हें देखिए. अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई आपका विरोध नहीं कर सकता, तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे. लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, लेकिन वह मनोबल नहीं है, तो आपके सभी हथियार और संसाधन बेकार हो जायेंगे और इसके लिए आपको नेतृत्व की जरूरत है. आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में एक ऐसा नेतृत्व है, जिसने 10 सालों में देश को कहां से यहां तक पहुंचाया है और उसे तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले आये हैं. हालांकि बदला लेना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली है. हमें अपने मूल्यों पर आधारित एक महान भारत का पुनर्निर्माण करके अपने देश का बदला लेना होगा. स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श हैं और मैं अक्सर उनके वचनों को दोहराता हूं. उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक है. हमें अक्सर सिखाया जाता है कि ईश्वर पर विश्वास करो, लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि पहले खुद पर विश्वास करना सीखो. क्योंकि आप भी उसी परम शक्ति का अंश हैं. यदि आप खुद को कमजोर मानेंगे, तो दुनिया आपको कमजोर ही समझेगी.

बेहद गंभीर मोड़ लेता ईरान का संकट

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो, एमपी-आइडीएसए
anandkmrai@gmail.com

ईरान के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि इसमें आर्थिक पतन, देशव्यापी जन-आंदोलन, सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर मतभेद और अंतरराष्ट्रीय दबाव एक साथ सक्रिय हैं. अब सिर्फ आर्थिक राहत की मांग नहीं की जा रही, इस्लामी शासन की वैधता पर ही सवाल उठाये जा रहे हैं. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के खिलाफ नारे लगना और मौलवी-शासित व्यवस्था के अंत की मांग करना इस बदलाव को स्पष्ट करता है. यह आंदोलन अब एक उत्तर-इस्लामी गणराज्य की कल्पना की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह अभी अस्पष्ट ही क्यों न हो.

ईरान इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद के सबसे नाजुक दौरों में से एक से गुजर रहा है. दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ आर्थिक संकट अब तेजी से राजनीतिक संकट में बदलता दिख रहा है. पश्चिम एशिया की प्रमुख शक्ति माने जाने वाले ईरान के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इसमें आर्थिक पतन, देशव्यापी जन-आंदोलन, सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर मतभेद और अंतरराष्ट्रीय दबाव, चारों तत्व एक साथ सक्रिय हैं. इस संकट की शुरुआत आर्थिक कारणों से हुई. वर्षों से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध, आंतरिक आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और संरचनात्मक कमजोरियों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को पहले ही खोखला कर दिया था. दिसंबर के अंत में जब महंगाई बेकाबू हुई, तब आवश्यक वस्तुओं की कमी बढ़ी और ईरानी मुद्रा में तेज गिरावट आई, तो असंतोष सड़कों पर फूट पड़ा. तेहरान के बाजारों से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन देखते ही देखते देश के लगभग सभी प्रांतों और प्रमुख शहरों तक फैल गये.

शुरुआत में प्रदर्शनकारी महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार और जीवन-यापन की बेहतर स्थितियों की मांग कर रहे थे. पर बहुत कम समय में ये मांगें राजनीतिक स्वरूप ले चुकी हैं. अब सड़कों पर केवल आर्थिक राहत की बात नहीं हो रही, बल्कि इस्लामी शासन की वैधता पर ही सवाल उठाये जा रहे हैं. सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के खिलाफ नारे लगना और मौलवी-शासित व्यवस्था के अंत की मांग करना इस बेचैनी को स्पष्ट करता है. शाह के जमाने के झंडों का लहराया जाना और रजा पहलवी की तस्वीरों का दिखना इस बात का संकेत है कि विरोध पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है. ईरानी शासन ने व्यापक दमनकारी उपाय अपनाये हैं- हजारों गिरफ्तारियां, सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग, डराने-धमकाने की नीति और पूरे देश में इंटरनेट बंद कर देना इसके सबूत हैं. न्यायपालिका और सुरक्षा प्रतिष्ठान के बयान बेहद सख्त हैं. प्रदर्शनकारियों को 'खुदा का दुश्मन' करार देने की चेतावनी दी गयी है, जो ईरानी कानून के तहत मृत्युदंड तक ले जा सकती है. यह भाषा संकेत देती है कि शासन इस आंदोलन को कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट मान रहा है. इस संकट को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि शासन के भीतर इस पर एक राय नहीं दिखती. राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से संयम बरतने और हिंसा से बचने की अपील की है. इसके पीछे या तो वास्तविक चिंता है या यह स्वीकारोक्ति कि केवल बल प्रयोग से वैधता बहाल नहीं की जा सकती. इसके उलट, न्यायपालिका, रिवोल्यूशनरी गार्ड और सर्वोच्च नेता के करीबी हलकों से कठोर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं. ईरानी व्यवस्था के लिए यह आंतरिक मतभेद खतरनाक हैं, क्योंकि अतीत में सत्ता प्रतिष्ठान की एकजुटता ही ऐसे आंदोलनों से निपटने का सबसे बड़ा आधार रही है.

दशकों से बिखरा हुआ और देश से बाहर रहा विपक्ष इस मौके को अवसर के रूप में देख रहा है. पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सामने आये हैं. उन्होंने शहरों के केंद्रों पर कब्जा करने और सार्वजनिक स्थानों पर डटे रहने की अपील की है. भले ही ईरान के भीतर उनकी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता सीमित हो, पर सड़कों पर राजशाही से जुड़े प्रतीकों का उभरना दिखाता है कि मानसिक स्तर पर बड़ा बदलाव हो रहा है. यह आंदोलन अब एक उत्तर-इस्लामी गणराज्य की कल्पना की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह अभी अस्पष्ट ही क्यों न हो. वैश्विक माहौल भी ईरान के लिए अनुकूल नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है. अमेरिकी विदेश और वित्त अधिकारियों के बयान भी ईरानी जनता के समर्थन और शासन पर दबाव की ओर इशारा करते हैं. यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने दमन की निंदा की है, जबकि मानवाधिकार संगठन इंटरनेट बंदी की आड़ में बड़े पैमाने पर हिंसा की आशंका जता रहे हैं. ईरान का यह दावा, कि अमेरिका और इस्राइल अशांति भड़का रहे हैं, घरेलू स्तर पर समर्थकों को संतुष्ट कर सकता है, पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसे खास समर्थन नहीं मिला है. इसने ईरानी नेतृत्व को दुविधा में डाल दिया है. कठोर दमन से अंतरराष्ट्रीय अलगाव और नये प्रतिबंधों का खतरा है, जबकि नरमी से आंदोलन के और तेज होने की आशंका. आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि शासन के पास असंतोष को शांत करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज देने की गुंजाइश भी नहीं बची है. इसी कारण यह संकट पिछले आंदोलनों की तुलना में खतरनाक है.

भारत के लिए यह स्थिति केवल दूर की राजनीतिक उथल-पुथल नहीं है. ईरान भारत की कनेक्टिविटी, ऊर्जा और भू-राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा है. चाबहार बंदरगाह, जिसमें भारत ने भारी निवेश किया है, पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे तक पहुंच का प्रमुख जरिया है. यदि ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता रहती है या सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव होता है, तो इन परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है और भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है. चीन का पहलू भी महत्वपूर्ण है. यदि ईरान और अधिक अलग-थलग पड़ता है, तो बीजिंग वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन बदल सकता है. ऐसे में भारत का उद्देश्य किसी विशेष ईरानी गुट का समर्थन करना नहीं, बल्कि स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना है, ताकि दीर्घकालिक रणनीतिक हित सुरक्षित रह सकें. अब तक भारत की नीति इसी व्यावहारिक सोच को दर्शाती है. तेहरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ संवाद बनाये रखना और उच्चस्तरीय संपर्क जारी रखना इसी रणनीति का हिस्सा है. साथ ही, भारत को अमेरिकी दबाव और मानवाधिकार संबंधी वैश्विक चिंताओं के बीच संतुलन साधना है. ब्रिक्स की अध्यक्षता के वर्ष में भारत स्वयं को वैश्विक दक्षिण की जिम्मेदार आवाज के रूप में पेश करना चाहता है, और ईरान के संदर्भ में यह संतुलन और भी संवेदनशील हो जाता है. अंततः, ईरान का मौजूदा संकट केवल अर्थव्यवस्था, प्रदर्शन या विदेशी दबाव का मामला नहीं है; यह वैधता का संकट है. एक ऐसी पीढ़ी सड़कों पर है, जो आर्थिक रूप से पिसी हुई, राजनीतिक रूप से हाशिये पर और सांस्कृतिक रूप से शासक व्यवस्था से कटी हुई महसूस करती है. शासन इस चुनौती से कैसे निपटता है, वह ईरान के भविष्य के साथ पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक दिशा को भी प्रभावित करेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)